web: www.nyaysakshi.com ‖ पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल ‖ पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, रविवार 26 सितंबर 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-04, अंक- 01

महत्वपूर्ण एवं खास

महाराष्ट्र में 18 महीने बाद 22 अक्टूबर से फिर से खुलेंगे सिनेमाघर

मुंबई (आरएनएस)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घोषणा की कि कोविड-19 महामारी और मार्च 2020 से कई बार लॉकडाउन के कारण बॉक्स-ऑफिस बंद होने के 18 महीने बाद राज्य के सभी सिनेमाघरों को 22 अक्टूबर से स्वास्थ्य मानदंडों के पूर्ण अनुपालन की उम्मीद करते हुए फिर से खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा, इस संबंध में एक विस्तृत एसओपी तैयार करने के लिए काम चल रहा है, जिसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। इस घोषणा के साथ फिल्म और थिएटर जगत में उत्साह की लहर फैल गई। मुख्यमंत्री ने इस घोषणा से पहले कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) डॉ. प्रदीप व्यास और शिवसेना सांसद संजय राउत और अन्य के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक में बॉलीवुड और मराठी फिल्म उद्योग से रोहित शेट्टी, मकरंद देशपांडे, सुबोध भावे, आदेश बांदेकर और मंच और सिल्वर स्क्रीन के अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे।

वैन व ट्रेलर की भिड़ंत में रीट परीक्षा देने जा रहे 6 की मौत

जयपुर (आरएनएस)। राजस्थान की राजधानी जयपुर के चाकसू में शनिवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को चाकसू के सेटेलाइट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये सभी लोग बारां से सीकर रीट की परीक्षा देने के लिए जा रहे थे। वैन में करीब 11 लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलने पर चाकसू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद सभी घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। सभी अभ्यर्थी बारां जिले के निवासी बताएं जा रहे हैं। ये छात्र रीट की परीक्षा देने सीकर जा रहे थे। जानकारी के अनुसार चाकसू के एनएच-12 पर निमोडिया कट के पास यह सड़क हादसा हुआ है। एक ईको वैन बेकाबू होकर ट्रेलर में जा घुसी। हादसे में वैन सवार चालक सहित 6 परीक्षार्थियों की मौत हो गई। वहीं, घटना में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायल 5 परीक्षार्थियों का महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार जारी है। एक परीक्षार्थी की हालत गंभीर बनी हुई है।

देश को 600 मेडिकल कॉलेजों व 50 एम्स जैसे संस्थानों की जरूरत : गडकरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि देश को कम से कम 600 मेडिकल कॉलेजों, 50 एम्स जैसे संस्थानों और 200 सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बुनियादी ढांचा विकास क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी जैसा मॉडल स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भी आजमाया जाना चाहिए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड शहर में कोविड-19 योद्धाओं के सम्मान में बोल रहे थे। गडकरी ने एक पुरानी बात का जिक्र करते हुए कहा, एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान मैंने उनसे वेंटीलेटर की कमी के बारे में बताया। उन्होंने मुझसे पूछा कि देश में कितने वेंटीलेटर हैं, इस पर मैंने कहा कि करीब ढाई लाख। उन्होंने कहा कि जब देश में कोरोना महामारी फैली तो सिर्फ 13 हजार वेंटीलेटर थे।

चक्रवाती तूफान गुलाब की चेतावनी, ओडिशा ने 7 जिलों में भेजे बचाव दल

भुवनेश्वर (आरएनएस)। बंगाल की खाड़ी पर बने चक्रवाती तूफान के ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों और पड़ोसी आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ने की चेतावनी के बीच ओडिशा सरकार ने सात जिलों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यह चेतावनी जारी की है। विशेष राहत आयुक्त ने कहा कि सरकार ने बचाव दलों को संवेदनशील इलाकों में भेजा और अधिकारियों से निचले इलाकों से लोगों को बाहर निकालने को कहा है। ओडिशा आपदा त्वरित कार्य बल (ओडीआरएएफ) के 42 दलों और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के 24 दलों के साथ दमकल कर्मियों को सात जिलों गजपति, गंजम, रायगढ़, कोरापुट, मल्कानगिरी, नबरंगपुर, कंधमाल भेजा। जेना ने बताया कि गंजम के चक्रवाती तूफान से गंभीर रूप से प्रभावित होने की उम्मीद है और इलाके में 15 बचाव दलों को तैनात किया गया है। इसके अलावा दमकल के 11 दलों के अलावा ओडीआरएएफ के छह दलों और एनडीआरएफ के 8 दलों को आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है।

गजपति और कोरापुट के जिला प्रशासनों ने 25 और 26 सितंबर को अवकाश रद्द कर दिए हैं। जिलाधीशों ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अपने-अपने मुख्यालय में रहने का निर्देश दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के उत्तर और मध्य हिस्से पर बना गहरे दबाव का क्षेत्र 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ा है। शनिवार को सुबह साढ़े आठ बजे गहरे दबाव का क्षेत्र गोपालपुर से 510 किलोमीटर पूर्व-दक्षिणपूर्व और आंध्र प्रदेश में कलिंगपत्तनम से 590

किलोमीटर पूर्व में स्थित था।

आईएमडी ने कहा, यह 26 सितंबर की शाम तक कलिंगपत्तनम के आसपास विशाखापत्तनम और गोपालपुर के बीच उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तटों की ओर बढ़ सकता है। आईएमडी के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय मोहपात्र ने बताया कि चक्रवाती तूफान के प्रभाव से 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवा चलने का अनुमान है। उन्होंने आगाह किया, चिन्हित जिलों में कई निचले इलाके डूब जाएंगे। ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र के पर्वतीय इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका है। गंजम और पुरी के शहरी इलाकों में भारी से बहुत भारी और कुछ हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश के कारण जलभराव हो सकता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने कुछ इलाकों में नदियों के उफान पर होने, भूस्खलन आने की आशंका को लेकर आगाह किया है। जीना ने बताया कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहे चक्रवात की तीव्रता तितली के समान होगी। तितली तूफान ने 2018 में राज्य में तबाही मचायी थी। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि इसके प्रभाव से शनिवार को ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। रविवार को भी दक्षिण ओडिशा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने और कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

बेकाबू बोलेरो ने 6 लोगों को कुचला, 3 की मौत

गोपालगंज (आरएनएस)। बिहार के गोपालगंज जिले के कटेया थाना क्षेत्र में बीती रात पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में निकली बोलेरो ने छह लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में वोट मांग रहे मुखिया प्रत्याशी के तीन समर्थकों की मौत हो गई जबकि तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, रात में एक मुखिया प्रत्याशी के समर्थक चुनाव प्रचार में निकले हुए थे। आरोप है कि भगवानपुर पंचायत के कुर्मी टोला में बीती रात में चुनाव प्रचार में शामिल एक बोलेरो पर से चालक का नियंत्रण हट गया और चुनाव प्रचार में शामिल छह लोगों को कुचल दिया।

इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि दो से तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं।

हथुआ के अनुमंडल पुलिस अधिकारी ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो को जब्त कर लिया है। मृतकों की पहचान कटेया थाने के मठिया गांव निवासी लाल बच्चन राम (28), निमईया गांव निवासी पारस गिरी (65) और पटोहवा गांव निवासी कपिल देव सिंह (69) के रूप में की गई है।

उन्होंने बताया कि सभी शवों को पुलिस ने अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है जबकि घायलों को इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कलेज रेफर किया गया है। पुलिस जब्त बोलेरो के विषय में यह पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि किस मुखिया प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में लोग रात में निकले थे।

पीएम मोदी की संपत्ति में 22 लाख का इजाफा

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति में इजाफा हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों और नई घोषणा के अनुसार पीएम मोदी की कुल संपत्ति में 22 लाख की वृद्धि हुई है। उनकी कुल संपत्ति 3.07 करोड़ रुपए हैं। पिछले साल यह कुल 2.85 करोड़ रुपए थी। पीएम मोदी के पास अपने कई मंत्रियों की तरह शेयर बाजार का जोखिम नहीं है। प्रधानमंत्री के पास 8.9 लाख रुपए का राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र है। इसके अलावा उनके पास 1.5 लाख रुपए की जीवन बीमा पॉलिसियां और एलएंडटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के बॉन्ड हैं। उन्होंने 2012 में 20,000 रुपए में इसे खरीदा था। पीएम मोदी के धन में वृद्धि मुख्य रूप से भारतीय स्टेट बैंक की गांधीनगर शाखा में उनके सावधि जमा के कारण हुई है। पीएम मोदी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, सावधि जमा राशि 31 मार्च को 1.86 करोड़ थी, जबकि पिछले साल यह 1.6 करोड़ रुपए थी। पीएम मोदी के पास कोई वाहन नहीं है। उसके पास 1.48 लाख की चार सोने की अंगूठियां हैं। 31 मार्च, 2021 को उनका बैंक बैलेंस 1.5 लाख रुपए था और हाथ में 36,000 रुपए की (पिछले साल की तुलना में कम) नकदी है। 2014 में पीएम बनने के बाद से मोदी ने कोई नई संपत्ति नहीं खरीदी है। 2002 में खरीदी गई उनकी एकमात्र आवासीय संपत्ति का मूल्य 1.1 करोड़ रुपए है। यह एक संयुक्त संपत्ति है और इसमें पीएम का केवल एक-चौथाई हिस्सा है। कुल 14,125 वर्ग फुट संपत्ति में से 3,531 वर्ग फुट पर पीएम मोदी का अधिकार है।

कानूनों को समय और लोगों की जरूरतों के अनुसार सुधारने की जरूरत : सीजेआई रमना

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एन वी रमना ने शनिवार को कहा कि विधायिका को कानूनों पर फिर से विचार करने और उन्हें समय और लोगों की जरूरतों के अनुरूप सुधारने की जरूरत है ताकि वे व्यावहारिक वास्तविकताओं से मेल खा सकें।

सीजेआई ने कटक में ओडिशा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के नए भवन का उद्घाटन करते हुए कहा कि संवैधानिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए कार्यपालिका और विधायिका को साथ-साथ काम करने की आवश्यकता है। जस्टिस रमना ने कहा कि मैं इस बात पर जोर देता हूं कि हमारे कानूनों को हमारी व्यावहारिक वास्तविकताओं से मेल खाना चाहिए। कार्यपालिका को संबंधित नियमों को सरल बनाकर इन्हें लागू कराना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कार्यपालिका और विधायिका के लिए संवैधानिक आकांक्षाओं को साकार करने में एक साथ कार्य करना महत्वपूर्ण था। सीजेआई ने कहा कि ऐसा करने पर ही न्यायपालिका कानून-निर्माता के रूप में कदम रखने के लिए मजबूर नहीं होगा और केवल

कानूनों को लागू करने और व्याख्या करने के कर्तव्य के साथ छोड़ दिया जाएगा। आखिर में यह देश के तीन अंगों का सामंजस्यपूर्ण कामकाज है जो न्याय के लिए प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर कर सकता है। यह कहते हुए कि भारतीय न्यायिक प्रणाली दोहरी चुनौतियों का सामना कर रही है, सीजेआई ने कहा कि पहला यह कि न्याय वितरण प्रणाली का भारतीयकरण करना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि आजादी के 74 साल बाद भी, पारंपरिक और कृषि प्रधान समाज, जो परंपरागत जीवन शैली का पालन कर रहे हैं, अदालतों का दरवाजा खटखटाने में झिझक महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे न्यायालयों की प्रथाएं, प्रक्रियाएं, भाषा उन्हें अलग लगती हैं। जटिल भाषा और न्याय वितरण की प्रक्रिया के बीच आम आदमी अपनी शिकायत की नियति को भूल जाता है। ऐसे हालात में न्याय की उम्मीद पाले बैठा व्यक्ति इस प्रणाली में खुद को बाहरी मान लेता है।

वित्त मंत्रालय ने 8 राज्यों में 2,903.80 करोड़ रुपये की पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को मंजूरी दी

नई दिल्ली (आरएनएस)। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 8 राज्यों को वित्त वर्ष 2021-22 के पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 2,903.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। मंत्रालय ने बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम और तेलंगाना के लिए 1,393.83 करोड़ रुपये की राशि जारी भी कर दी है। पूंजीगत व्यय के उच्च गुणक प्रभाव को देखते हुए और कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर राज्य को बहुत आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए 29 अप्रैल, 2021 को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 'पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को

50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है लेकिन कुल वित्तीय सहायता वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 15 हजार करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तीन भाग हैं

भाग-1 योजना का यह भाग 8 पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा और पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए है। इस भाग के तहत 7 पूर्वोत्तर राज्यों में से प्रत्येक को 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। असम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों को प्रत्येक के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

भाग-2 योजना का यह भाग अन्य सभी राज्यों के लिए है जो भाग- ढ्ढ में शामिल नहीं हैं। इस हिस्से के लिए 7,400 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। यह राशि इन राज्यों के बीच वर्ष 2021-22 के लिए 15वें वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार केंद्रीय करों में उनके हिस्से के अनुपात में आवंटित की गई है।

भाग-3 योजना का यह भाग राज्य सरकारों को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) के निजीकरण/विनिवेश और संपत्ति के मुद्रीकरण/पुनर्चक्रण के प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए है। इस भाग के तहत, राज्यों को योजना के तहत भाग- ढ्ढ या भाग- ढ्ढढ्ढ के तहत उनके आवंटन के अलावा अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी। योजना के इस हिस्से के लिए 5,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इस भाग के लिए, किसी राज्य को विशिष्ट राशि आवंटित नहीं होगी, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर राशि प्रदान किया जाएगी।

पिछले वित्त वर्ष में भी वित्त मंत्रालय द्वारा 2020-21 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता नामक योजना शुरू की गई थी।

योजना के तहत, व्यय विभाग द्वारा 27 राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 11,911.79 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई जिसमें से 2020-21 में राज्यों को 11,830.29 करोड़ रुपये जारी की गई।

यूपी 10 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीनेशन करने वाला बना देश का पहला राज्य

लखनऊ (आरएनएस)। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल 2,15,209 सैंपल की जांच की गयी है। जिसमें कोरोना संक्रमण के 14 नये मामले आये हैं। प्रदेश में अब तक कुल 7,75,81,132 सैंपल की जांच की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 26 व अब तक कुल 16,86,694 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 177 एक्टिव मामले हैं व 155 लोग होम आइसोलेशन में है। प्रसाद ने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर किया जा रहा है। प्रदेश 10 करोड से अधिक कोविड वैक्सीनेशन करने वाला देश में पहला राज्य है। उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन के लिए लगे सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को 10 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन करने पर धन्यवाद दिया है। कल तक कुल 10,00,36,235 कोविड डोज दी गयी है। प्रदेश में कल तक पहली डोज 8,15,25,547 व दूसरी डोज 1,85,10,688 लगायी गयी हैं। प्रसाद ने बताया कि प्रदेश सरकार ने मच्छर जनित रोग व जल जनित रोग से बचाने के लिए आवश्यक चिकित्सकीय प्रबंध किये गये हैं।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लेह-लद्दाख में दूसरे अल्टीमेट लद्दाख साइक्लिंग चैलेंज को झंडी दिखाकर रवाना किया

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आजादी का अमृत महोत्सव और फिट इंडिया अभियान के तहत दूसरे अल्टीमेट लद्दाख साइक्लिंग चैलेंज को झंडी दिखाकर रवाना किया।साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के समन्वय से लद्दाख पुलिस द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है।

साइकिल चलाने की प्रतियोगिता को झंडी दिखाकर रवाना करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने परिकल्पना, फिट इंडिया अभियान की प्रेरणाहै। यह कार्यक्रम देशवासियों में बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है। मंत्री ने कहा कि वे समुद्र तल से 11000 फीट की ऊंचाई पर साइकिल चलाने की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लद्दाख के युवाओं के जोश को देखकर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मंत्री ने साइकिल प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर फिट इंडिया अभियान में योगदान देने के लिए लद्दाख के युवाओं की सराहना की।

केन्द्रीय मंत्री ने फिट इंडिया अभियान के तहत साइकिल चलाने की इस प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख पुलिस और एलएएचडीसी को भी बधाई दी।

फिट इंडिया अभियान को बढ़ावा देने में युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए ठाकुर ने कहा, आइए साइकिल चलाएं, हम स्वस्थ रहें और भारत को स्वस्थ रखें। युवा स्वस्थ हैं, तो भारत स्वस्थ है।

केन्द्रीय मंत्री ने, सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल और सीईसी,ताशी ग्यालसन के साथ साइकिल चलाने की इस प्रतियोगिता में भाग लिया।

केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लद्दाख के हम्बोटिंग ला में दूरदर्शन/आकाशवाणी ट्रांसमीटर का शुभारंभ किया

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लद्दाख में कारगिल के पास हम्बोटिंग ला में दूरदर्शन और आकाशवाणी के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर राष्ट्र को समर्पित किए। 10 किलोवाट के ट्रांसमीटर देश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थापित टीवी और रेडियो ट्रांसमीटर हैं, जो औसत समुद्र तल से 4,054 मीटर (लगभग 13,300 फुट) की ऊंचाई पर स्थित हैं। लेह में लगे ट्रांसमीटर 3,501 मीटर (लगभग 11,450 फुट) की ऊंचाई पर स्थित हैं। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति और भौगोलिक इलाके को देखते हुए हम्बोटिंग ला स्थल सबसे दुर्गम स्थानों में से एक है। अनुराग ठाकुर ने मौसम की प्रतिकूल स्थिति के बीच परियोजना को पूरा करने के लिए इंजीनियरों और श्रमिकों की टीम की सराहना की। ट्रांसमीटरों की दायरा त्रिज्या में 50 किलोमीटर से अधिक है। यह देखते हुए कि ट्रांसमीटर कारगिल के सुदूर सीमा क्षेत्र में लगभग 50,000 की आबादी को कवर करेंगे, ठाकुर ने कहा कि यह संख्या देश के अन्य हिस्सों की तुलना में छोटी लग सकती है, लेकिन यह सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिक तक पहुंचने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। ठाकुर ने यह भी घोषणा की कि डीडी कश्मीर में लद्दाख का प्रतिदिन का योगदान 1 अक्टूबर, 2021 से 30 मिनट से दोगुना कर एक घंटे तक कर दिया जाएगा। ठाकुर ने कहा कि रेडियो और टेलीविजन के मजबूत सिग्नल द्वारा सीमावर्ती इलाकों में कवरेज सरकार की प्रसारण नीतियों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि यह न केवल जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को उचित जानकारी प्रदान करने के लिए, बल्कि पड़ोसी दुश्मन देशों के दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए भी आवश्यक है। सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थलीय कवरेज को सुदृढ़ करने से दर्शकों/श्रोताओं को देश की नीतियों, समाचारों और समसामयिक मामलों के बारे में अच्छी तरह से सूचित किया जा सकता है और साथ ही साथ विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा उनका मनोरंजन किया जा सकता है।

यह इस क्षेत्र के छात्रों को दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से शैक्षिक सामग्री भी उपलब्ध कराएगा। अपने टीवी, रेडियो और डिजिटल मंचों के माध्यम से, प्रसार भारती विभिन्न राज्य शिक्षा विभागों और संस्थानों के सहयोग से स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों के लिए विभिन्न शैक्षिक सामग्री की पेशकश कर रहा है।

इस अवसर पर लद्दाख के सांसद जे टी नामग्याल ने कहा कि नए ट्रांसमीटर क्षेत्र के विकास को लेकर केंद्र की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।